भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 124
12 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: संस्थागत ऋण और कृषि ऋण

*124. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कृषि में संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाए जाने के तौर-तरीकों का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत वर्ष में किसानों को संवितरित संस्थागत ऋण का ब्यौरा क्या है और कितने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आवेदन अनुमोदित किए गए हैं और संस्वीकृत तदनुसूची ऋण राशि कितनी है;

(ग) सरकार ने देश में किसानों की आय में वृद्धि के मुद्दे का किस प्रकार समाधान किया है;

(घ) क्या इन पहलों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप गैर-कृषि रोजगार अवसरों की तलाश में गांव से शहर की ओर पलायन में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) कृषि ऋणों तक किसानों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की भावी योजनाओं और कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत वर्ष में प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से किसानों को प्रदान की गई आय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“संस्थागत ऋण और कृषि ऋण” के संबंध में दिनांक 12.12.2023 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 124 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकार कृषि में संस्थागत ऋण के विकास के लिए उचित उपाय करती है। यहां, केंद्र सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाती है। केंद्र सरकार ने हर वर्ष बजट में कृषि ऋण के लिए वार्षिक लक्ष्य की घोषणा करके कृषि में संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ग्राउंड लेवल क्रेडिट (जीएलसी)/कृषि ऋण प्रवाह में वर्ष दर वर्ष लगातार प्रगति देखी गई है और जीएलसी 2013-14 में 7.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 20.00 लाख करोड़ हो गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) किसानों को समय पर ऋण प्रदान करता है ताकि वे अल्पकालिक/दीर्घकालिक खेती की आवश्यकता, फसलोपरांत खर्च, उपभोग की आवश्यकता आदि को पूरा कर सकें और अपनी उपभोग आवश्यकताओं से निपटने के लिए नकदी निकाल सकें। केसीसी योजना को सरल बनाया गया है और इसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) सक्षम डेबिट कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एकमुश्त दस्तावेज़ीकरण, सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि, सीमा के भीतर कई बार पैसा निकालने आदि की सुविधाएं शामिल हैं। वर्ष 2018-19 से, भारत सरकार ने पशुपालन और मत्स्य किसानों को अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी योजना शुरू की। दिनांक 31.3.2023 तक लगभग 7.34 करोड़ सक्रिय केसीसी धारक हैं, जिनकी बकाया राशि 8.85 लाख करोड़ है।

संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए केसीसी के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण दिया जाता है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय संस्थानों को 1.5% की दर से ब्याज छूट दी जा रही है। इसलिए, अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों को प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण उपलब्ध हैं। ऋणों की शीघ्र और समय पर चुकौती के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) भी दिया जाता है; इस प्रकार ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। केवल संबद्ध गतिविधियों (फसल पालन के अलावा) हेतु प्राप्त अल्पकालिक ऋण के मामले में, 2.00 लाख रुपये तक की ऋण 7% की दर से उपलब्ध हैं। इस पर अतिरिक्त 3% पीआरआई भी उपलब्ध है। किसानों द्वारा मजबूरन अपनी उपज बेचने को हतोत्साहित करने और

उन्हें गोदामों में अपनी उपज का भंडारण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, फसलोपरांत किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों को छह महीने तक की अवधि के लिए 3% की ब्याज छूट का लाभ उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए योजना के तहत 23,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।

(ख): दिनांक 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक एजेंसी-वार संवितरण में वाणिज्यिक बैंकों के लिए 16.76 लाख करोड़ रुपये, सहकारी बैंकों के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए 2.42 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। इस प्रकार, इस अवधि के दौरान राज्य और एजेंसियों के लिए कुल वितरण 21.55 लाख करोड़ रुपये है। दिनांक 31.3.2023 तक लगभग 7.34 करोड़ सक्रिय केसीसी धारक हैं जिन पर 8.85 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि है। सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की संख्या का विवरण **अनुबंध-1** पर है।

(ग) एवं (घ) : सरकार ने "किसानों की आय दोगुनी करने (डीएफआई)" से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इसे प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी जिसमें विभिन्न नीतियों, सुधारों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिशें शामिल थीं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, समिति ने आय वृद्धि के निम्नलिखित सात स्रोतों की पहचान की: -

- i. फसल उत्पादकता में वृद्धि
- ii. पशुधन उत्पादकता में वृद्धि
- iii. संसाधन उपयोग दक्षता - उत्पादन लागत में कमी
- iv. फसलन गहनता में वृद्धि
- v. उच्च मूल्य वाली कृषि में विविधीकरण
- vi. किसानों की उपज पर लाभकारी मूल्य
- vii. अधिशेष जनशक्ति का कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में स्थानांतरण

सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए उच्च आय प्राप्त करने के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं को अपनाया और कार्यान्वित किया है। सरकार के निम्नलिखित प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए अभूतपूर्व रूप से उन्नत बजटीय प्रावधान किए गए हैं:-

- i. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता
- ii. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
- iii. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण
- iv. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना
- v. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना

- vi. प्रति बूंद अधिक फसल
- vii. सूक्ष्म सिंचाई निधि
- viii. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना
- ix. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
- x. कृषि यंत्रीकरण
- xi. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना
- xii. राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-एनएएम) विस्तार प्लेटफॉर्म की स्थापना
- xiii. राष्ट्रीय खाद्य तेल-ऑयल पाम मिशन का शुभारंभ
- xiv. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
- xv. कृषि उपज रसद में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।
- xvi. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:
- xvii. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इको सिस्टम का निर्माण
- xviii. कृषि एवं संबद्ध कृषि जिनसों के निर्यात में उपलब्धि

इन योजनाओं के क्रियान्वयन से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है, जिन्होंने अपनी आय दो गुना से अधिक बढ़ाई है।

(ड.): पीएम किसान लाभार्थियों को संतुष्ट करने पर विशेष ध्यान देने के साथ एक केसीसी संतुष्टि अभियान अर्थात् "घर घर केसीसी अभियान" शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी से संतुष्ट करने के लिए ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति के तहत एक विशेष अभियान के माध्यम से संभावित किसानों को एकजुट करना और सभी प्रकार की केसीसी योजनाओं (फसल की खेती, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन आदि के लिए) के तहत अधिकतम संख्या में किसानों/पीएम किसान लाभार्थियों को नामांकित करना है।

(च): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इस योजना के तहत 6000/- रुपये प्रति वर्ष की राशि, जो 2000/- रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाती है। दिनांक 23.11.23 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए जा चुके हैं।

पिछले वर्ष पीएम-किसान के तहत जारी धनराशि का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-॥** में दिया गया है।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार सक्रिय केसीसी		
(पूर्ण संख्या और राशि करोड़ रुपये में)		
राज्य का नाम	योग	
	केसीसी की संख्या	बकाया
अंडमान और निकोबार	9056	38
आंध्र प्रदेश	45,51,558	60883
अरुणाचल प्रदेश	10100	81
असम	6,46,919	3895
बिहार	25,76,527	17388
चंडीगढ़	1475	99
छत्तीसगढ़	19,17,435	10757
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1581	40
दिल्ली	2861	45
गोवा	9458	111
गुजरात	30,18,544	62391
हरियाणा	22,86,953	50045
हिमाचल प्रदेश	4,60,441	7636
जम्मू एवं कश्मीर	9,10,514	6363
झारखंड	9,67,591	5200
कर्नाटक	47,21,067	54181
केरल	25,94,466	43401
लद्दाख	28072	258
लक्षद्वीप	1770	15
मध्य प्रदेश	62,68,740	78136
महाराष्ट्र	71,77,298	70354
मणिपुर	19693	165
मेघालय	71677	360
मिजोरम	35093	315
नागालैंड	30070	179
ओडिशा	39,71,032	21744
पुदुचेरी	13286	286
पंजाब	21,98,101	55428
राजस्थान	65,40,646	99551
सिक्किम	8702	56
तमिलनाडु	35,80,708	42143
तेलंगाना	43,37,476	44405
त्रिपुरा	1,55,042	507
उत्तराखंड	5,08,644	6365
उत्तर प्रदेश	1,07,05,196	1,28,123
पश्चिम बंगाल	31,32,363	14531
कुल	7,34,70,155	8,85,475

स्रोत: पीएसबी के लिए आरबीआई और आरआरबी और सहकारी समितियों के लिए नाबार्ड

पिछले वर्ष में पीएम-किसान के तहत लाभार्थियों और जारी की गई राशि का राज्य-वार विवरण			
क्र.सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गयी राशि (रुपये करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14,992	8.56
2	आंध्र प्रदेश	47,83,549	2,959.81
3	बिहार	83,54,676	4,851.82
4	चंडीगढ़	367	0.2
5	छत्तीसगढ़	29,47,050	1,616.42
6	दिल्ली	14,976	8.44
7	गोवा	9,118	4.74
8	गुजरात	59,62,338	3,167.84
9	हरियाणा	18,62,403	986.2
10	हिमाचल प्रदेश	9,46,579	469.83
11	जम्मू और कश्मीर	11,07,122	528.45
12	झारखंड	22,61,579	1,327.11
13	कर्नाटक	51,89,062	3,414.03
14	केरल	34,97,757	1,598.63
15	लद्दाख	17,673	10.38
16	लक्षद्वीप	848	0.66
17	मध्य प्रदेश	85,40,733	4,876.64
18	महाराष्ट्र	1,04,51,308	5,655.85
19	ओडिशा	33,89,362	1,792.28
20	पुदुचेरी	10,235	5.89
21	पंजाब	17,07,679	691.22
22	राजस्थान	72,59,774	3,792.36
23	तमिलनाडु	32,29,940	1,574.45
24	तेलंगाना	35,81,177	2,011.57
25	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	12,958	8.64
26	उत्तर प्रदेश	2,43,00,100	12,450.90
27	उत्तराखंड	9,00,559	475.42
28	पश्चिम बंगाल	48,69,285	2,839.10
	कुल(1)	10,52,23,199	57,127
पूर्वोत्तर राज्य			
29	अरुणाचल प्रदेश	95,095	53.06
30	असम	10,28,127	560.57
31	मणिपुर	3,67,646	192.87
32	मेघालय	56,079	18.57
33	मिजोरम	88,121	45.8
34	नागालैंड	1,97,090	103.42
35	सिक्किम	11,702	8.57
36	त्रिपुरा	2,34,743	147.59
	कुल (2)	20,78,603	1,130
	सकल योग (1+2)	10,73,01,802	58,258